वैश्वीकरण और भारतीय कृषि (Globalization and Indian Agriculture)

भारत की नवीन आर्थिक नीति का मूलभूत उद्देश्य उदारीकरण की नीति अपनाकर निजीकरण को प्रोत्साहित करना तथा देश की अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था तथा विश्व बाजार से अच्छी तरह जोड़ने तथा उसे अधिक प्रतियोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण करना आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है।

भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि (Globalization and Indian Agriculture):-

आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने से भारतीय व्यवस्था जो नियम, प्रतिबंध, लाइसेंस राज की जटिलता से ग्रस्त थी अब कुछ हद तक खुलकर सांसे लेने लगी है। भूमंडलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण का देश की अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परंतु कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्न तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है:-

(I) कृषि एवं सम्बंध क्षेत्र की वृद्धि दर (Growth rate of agriculture and allied sector):-

भूमंडलीकरण के पश्चात भारतीय कृषि क्षेत्र विकास दर निम्न तथा अस्थिर बनी हुई है आर्थिक सुधारों से पूर्व सातवीं योजना के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत थी जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर मात्र 2.4 प्रतिशत तथा 11वीं योजना में यह 3.6 प्रतिशत परिलक्षित हुई। अत: आर्थिक सुधार एवं भूमंडलीकरण के काल में कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तथा यह क्षेत्र प्राय: उपेक्षित रहा।

(II) खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर (Growth rate of food grains production):-

देश में ध्यान का उत्पादन जो 1980-81 में 1,296 लाख था वह बढ़कर 2011-12 में 2,593 लाख टन हो गया यद्यपि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुआ, परंतु काफी उतार चढ़ाव के साथ हुआ जो

कृषि विकास की दृष्टि से काफी चिंताजनक है। आर्थिक सुधारों की उपरांत देश में खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकता एवं कृषि क्षेत्र वृद्धि दर को निम्न आंकड़ों से देखा जा सकता है:-

भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन उत्पादकता एवं क्षेत्र की औसत विकास दर (प्रतिशत में)

वर्ष	**1990-91 से 1999-2000**	**2002-03 से 2006-07**	**2007-08 से 2011-12**
कुल खाद्यान्न	2.19	1.29	3.8
पैदावार (उत्पादकता)	2.49	0.59	3.55
क्षेत्र	-0.27	0.29	0.19

स्रोत :- एग्रीकल्चरल स्टैटिसटिक्स (2012-13)

आर्थिक सुधारों के उपरांत समग्र कृषि उत्पादन की वृद्धि दरों में हुए नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव को विभिन्न फसलों के उत्पादन की वृद्धि दरों द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है :-

भारत में विभिन्न फसलों के उत्पादन की औसत वृद्धि दरें

फसल	आर्थिक सुधार के पूर्व	आर्थिक सुधार के बाद
	1980-81 से 1990-91	2007-08 से 2011-12
खाद्यान्न	3.1	3.8
चावल	3.3	2.69
गेहूँ	4.3	4.64
मोटे अनाज	1.2	5.68
दालें	3.0	4.28
तिलहन	7.1	5.54

गन्ना	4.6	0.99
कपास	3.4	10.46
जूट तथा मेस्ता	1.2	1.26

स्रोत :- एग्रीकल्चरल स्टैटिसटिक्स (2012-13)

उपर्युक्त परिस्थितियों के लिए कई कारक उत्तरदायी माने जा सकते हैं –

पहला, सुधार प्रक्रिया में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के विकास पर बल दिया तथा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की।

दूसरे, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निर्माण जो 90 के दशक के प्रारंभ में सकल घरेलू उत्पाद का 1.92 प्रतिशत था वह घटकर 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत हो गया। पुनः 2003-04 के दौरान यह 1.9 प्रतिशत ही रहा। यह गिरावट विशेषकर कृषि में सार्वजनिक निवेश में कमी के कारण हुई। सार्वजनिक कृषि निवेश में गिरावट ने ग्राम विकास और सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिससे कृषि और विशेषकर खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर मंद पड़ गई। यह स्थिति कृषि क्षेत्र के विकास के लिए चिंताजनक है।

तीसरा, नाबार्ड ने ग्रामीण आधार संरचना और विकास निधि में 13,500 करोड रुपए इकट्ठे कर लिए, परंतु वह केवल 30% ही उपयोग कर पाया। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा कृषि विकास के लिए निवेश में गिरावट इस उद्देश्य से लाई गई कि सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाली कमी की निजी क्षेत्र क्षतिपूर्ति कर देगा तथा सिंचाई आदि का विस्तार करेगा, परंतु ऐसा ना हो सका, विशेषकर –बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दरों पर धीमा प्रभाव पड़ा तथा हरित क्रांति वाले राज्य, जैसे:- पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश अपने अधिकतम उत्पादकता स्तर पर पहुंच गए हैं। इन राज्यों में उत्पादकता के स्तर के बढ़ने की गुंजाइश सीमित है। इस तरह सुधार प्रक्रिया पिछड़े राज्यों में हरित क्रांति की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में विफल रही।

आर्थिक सुधार से पूर्व यदि हम पानी, बीज, उर्वरक, प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होता है कि आर्थिक सुधार से पूर्व यह क्षेत्रफल में औसत वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत थी जो आर्थिक सुधार के बाद गिरकर 2.7 प्रतिशत हो गई तथा 2008-09 तक इसमें केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हो पाई।

(III) भूमंडलीकरण एवं कृषि वस्तुओं का विदेशी व्यापार (Globalization and foreign trade of agricultural commodities):-

वैश्वीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्व व्यापार में वृद्धि करना है। इस संबंध में भारत के कृषि व्यापार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना उपयुक्त होगा।

(a) कृषि वस्तुओं का निर्यात (Export of agricultural commodities):-

भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति अपनाने के पश्चात यह उम्मीद की गई थी कि इससे कृषि निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी।

उदारीकरण से पूर्व भारत के कृषि निर्यात की वृद्धि दर 1960-61 से 1970-71 के बीच मात्र 0.78% थी जो 1970-71 से 1980-81 के बीच तेजी से बढ़ कर 17.92 प्रतिशत प्रति वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गई। परंतु कृषि निर्यात की वृद्धि दर 1980-81 से 1990-91 के दौरान घटकर 2.24% प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई। तथा आर्थिक सुधारों के उपरांत 1990-91 से 2000-01 के दौरान कृषि निर्यात की वृद्धि दर पुनः बढ़कर 7.7% प्रतिशत प्रतिवर्ष के अपेक्षाकृत उच्चतर स्तर पर पहुंच गई। यह वृद्धि दर 2000-01 से 2011-12 के बीच बढ़कर 45.57 प्रतिशत औसत प्रतिवर्ष हो गई। इस तरह नई नीति का कृषि वस्तुओं के निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आर्थिक उदारीकरण के पूर्व एवं पश्चात भारत के कृषि वस्तुओं की निर्यात की प्रवृत्ति को निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है:-

भारत के प्रमुख कृषि निर्यात

वर्ष	कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत
1960-61	44.2
1970-71	31.7
1980-81	30.6
1990-91	19.4
2000-01	14.0
2011-12	10.7

स्रोत :- आर्थिक समीक्षा (Various Issues)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि कुछ वर्षों में कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई परंतु उसके उपरांत कृषि वस्तुओं के निर्यात में लगातार गिरावट आई है।

(b) विश्व के कृषि निर्यात में भारत का अंश (India's share in the world's agricultural exports):-

विश्व के कृषि बाजार में भारत का अंश अत्यल्प है। 1990 में अनाज एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुओं के विश्व निर्यात व्यापार में भारत का अंश मात्र 0.6 प्रतिशत था जो बढ़कर 2011 में 4.7 प्रतिशत हो गया। उल्लेखनीय है कि इस निर्यात व्यापार में भारत के कुछ ही वस्तुओं के अंश में बढ़ोतरी हुई है, जैसे:-चावल के निर्यात में वर्ष 1990 में भारत का 6.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 2011 में 16.8 प्रतिशत हो गया। जबकि इसके विपरीत विश्व निर्यात व्यापार में भारतीय चाय का अंश जो 1980 में 27.7 प्रतिशत था वह घटकर 2011 में 11 प्रतिशत रह गया।

(c) कृषि वस्तुओं का आयात (Import of agricultural commodities):-

वर्ष 1991के बाद कृषि वस्तुओं के निर्यात में हुई वृद्धि के साथ ही साथ भारत के कृषि वस्तुओं के आयात में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 से 2010-11 के बीच कृषि वस्तुओं के आयात की वृद्धि दर 0.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा खाद्य तेलों के आयात की वृद्धि दर 174.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, जबकि इसी दौरान कृषि वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि दर 30.5% प्रतिवर्ष रही। विगत वर्षों में देश में भारी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया है जिसके फलस्वरूप कृषि पदार्थों के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(IV) कृषि रोजगार (Agricultural employment):-

आर्थिक उदारीकरण के काल में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रोजगार की दर में बहुत गिरावट आ गई। देश के कुल श्रमिकों के लगभग 55% को रोजगार उपलब्ध कराने वाली कृषि में रोजगार की वृद्धि दर जो 1983-94 के 1.51प्रतिशत थी वह घटकर 1994-2000 के बीच -0.34 प्रतिशत हो गई।

निष्कर्ष (Conclusion):-

इस प्रकार संक्षेप यह कहा जा सकता है कि आर्थिक सुधारों की पश्चात भूमंडलीकरण के काल में देश में कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहा तथा इसके विकास की दर धीमी और उतार-चढ़ावों से भरी रही। कृषि की वृद्धि दर में आई गिरावट ने कृषि क्षेत्र में रोजगार की दशा को और भी दयनीय बना दिया। कृषि में व्यापार की शर्तों में उदारीकरण के काल में कोई सुधार नहीं हुआ। यह इस ओर संकेत करती है कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि अभी भी एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा कृषक एवं अन्य कृषि मजदूर जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें देश की नई आर्थिक नीति -भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण से किसी तरह का लाभ नहीं पहुंच सका है।